VAJIRAO & REDDY INSTITUTE
India's Top Potential Training Institute for IAS

+918988885050
+918988886060

www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

TODAY'S ANALYSIS

(आज का विश्लेषण)

(14 December 2024)

Sources:

The Hindu, The Indian Express, The Economics Times & PIB

Important News:

- रेलवे (संशोधन) विधेयक 2024 और इसका भारतीय रेलवे पर प्रभाव
- स्विटजरलैंड ने भारत से MFN का दर्जा वापस लिया
- ला नीना को लेकर भविष्यवाणी में गलती क्यों हुई?
- MCQ

ADDRESS:
19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

रेलवे (संशोधन) विधेयक 2024 और इसका भारतीय रेलवे पर प्रभाव:

चर्चा में क्यों है?

- संसद के अंदर सरकार और विपक्ष के बीच गरमागरम बहस के बीच, 13 दिसंबर को लोकसभा ने रेलवे (संशोधन) विधेयक, 2024 पारित कर दिया। यह विधेयक भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम, 1905 को निरस्त करने और इसके प्रावधानों को रेलवे अधिनियम, 1989 में शामिल करने का प्रयास करता है।
- उल्लेखनीय है कि इस विधेयक की सामग्री को बहुत आलोचना नहीं मिली, लेकिन कई सांसदों ने इस विधेयक के बारे में चिंता व्यक्त की कि यह रेलवे से संबंधित बड़े मुद्दों जैसे सुरक्षा, रिक्तियों और क्षेत्रीय और मंडल स्तरों पर सत्ता के विकेंद्रीकरण को संबोधित करने में विफल रहा है।

इस विधेयक का उद्देश्य क्या है?

- इस विधेयक का उद्देश्य भारतीय रेलवे में दक्षता लाना है।
- **उद्देश्य:**

1. रेलवे अधिनियम, 1989 में संशोधन करके रेलवे बोर्ड को वैधानिक समर्थन प्रदान करना, जिसने अपनी स्थापना के बाद से ही बिना किसी मंजूरी के काम किया है।
2. परिचालन दक्षता में सुधार करना और शक्तियों का विकेंद्रीकरण करना, रेलवे क्षेत्रों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करना।
3. शुल्क, सुरक्षा और निजी क्षेत्र की भागीदारी सहित भारतीय रेलवे के विभिन्न पहलुओं की देखरेख के लिए एक स्वतंत्र नियामक की स्थापना करना।

केंद्र सरकार को विधेयक लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी?

- उल्लेखनीय है कि भारत के रेलवे नेटवर्क का निर्माण स्वतंत्रता से पहले लोक निर्माण विभाग की एक शाखा के रूप में शुरू हुआ था। जब नेटवर्क का विस्तार हुआ, तो विभिन्न रेलवे संस्थाओं के समुचित संचालन को सक्षम करने के लिए भारतीय रेलवे अधिनियम, 1890 को अधिनियमित किया गया। बाद में, भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम, 1905 को अधिनियमित किया गया, ताकि रेलवे बोर्ड को भारतीय रेलवे अधिनियम, 1890 के तहत कुछ शक्तियां या कार्य प्रदान किए जा सकें।

- यद्यपि 1989 में रेलवे अधिनियम लागू होने के बाद 1890 का अधिनियम निरस्त कर दिया गया, परन्तु रेलवे बोर्ड अधिनियम, 1905 अस्तित्व में रहा तथा बोर्ड के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति इसी कानून के तहत होती रही।

रेलवे विधेयक में प्रस्तावित सुधार और संरचनात्मक परिवर्तन:

स्वतंत्र नियामक का गठन:

- इस विधेयक में हितधारकों के हितों की रक्षा और प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने के लिए एक स्वतंत्र नियामक के गठन के प्रावधान शामिल हैं।

रेलवे जोन को स्वायत्तता:

- रेलवे जोनों के लिए स्वायत्तता में वृद्धि की मांग लंबे समय से की जा रही है, जिसका समर्थन 2014 की श्रीधरन समिति सहित विभिन्न समितियों ने किया है।
- इस विधेयक में वित्तीय और परिचालन संबंधी निर्णय लेने का अधिकार जोनों को देने का प्रस्ताव है, जिससे उन्हें बजट, बुनियादी ढांचे के काम और भर्ती का प्रबंधन करने का अधिकार मिलेगा।

रेलवे बोर्ड की नियुक्ति और संरचना:

- सरकार रेलवे बोर्ड के सदस्यों की संख्या, योग्यता और सेवा की शर्तें तय करेगी। यह बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया की देखरेख भी करेगी, जिससे शासन और जवाबदेही को सुव्यवस्थित किया जा सकेगा।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

क्षेत्रीय विकास:

- इस विधेयक में धारा 24ए पेश की गई है, जिससे सरकार सुपरफास्ट ट्रेन संचालन और बुनियादी ढांचे के उन्नयन में तेजी ला सकेगी, जैसे कि अरुणाचल एक्सप्रेस को सीवान-थावे-कप्तानगंज-गोरखपुर मार्ग से आगे बढ़ाना।

रेलवे को लेकर विपक्ष की चिंताएँ:

- **निजीकरण की आशंका:** कांग्रेस सांसदों ने तर्क दिया कि यह विधेयक भारतीय रेलवे के निजीकरण का मार्ग प्रशस्त कर सकता है, जिससे गरीबों के लिए इसकी पहुँच कम हो जाएगी।
- **स्वायत्तता पर प्रभाव:** कई सांसदों ने आशंका व्यक्त की कि रेलवे बोर्ड की नियुक्तियों पर सरकार का बढ़ता नियंत्रण भारतीय रेलवे की स्वायत्तता को खत्म कर सकता है।
- **यात्री रियायत से जुड़ी आशंका:** कई सांसदों ने वरिष्ठ नागरिकों, पत्रकारों और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए किराए में रियायतें बहाल करने की माँग की, जिन्हें महामारी के दौरान बंद कर दिया गया था।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

विधेयक को लेकर सरकार का बचाव:

- रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने निजीकरण के आरोपों को खारिज करते हुए दोहराया कि विधेयक का उद्देश्य भारतीय रेलवे को अधिक कुशल और आत्मनिर्भर बनाना है, साथ ही इसकी सामाजिक जिम्मेदारी को भी बरकरार रखना है। सरकार का कहना है कि विधेयक से रेलवे के शासन में सुधार होगा और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा।

स्विटजरलैंड ने भारत से MFN का दर्जा वापस लिया:

चर्चा में क्यों है?

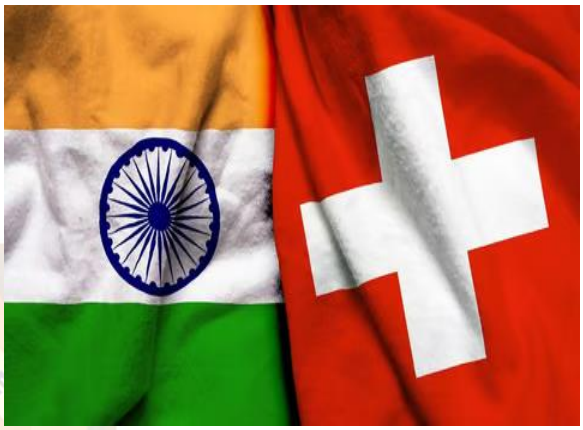

- स्विटजरलैंड ने भारत को दिया गया सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र (MFN) का दर्जा वापस लेने का फैसला किया है, इस कदम से स्विट्जरलैंड में काम करने वाली भारतीय कंपनियों पर महत्वपूर्ण कर प्रभाव पड़ेगा। यह निर्णय स्विस खाद्य दिग्गज नेस्ले से जुड़े कर विवाद के संबंध में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रतिकूल फैसले के बाद आया है।
- उल्लेखनीय है कि 1 जनवरी, 2025 से, स्विट्जरलैंड में भारतीय व्यवसायों को विशेष रूप से लाभांश आय पर उच्च कर कटौती दरों का सामना करना पड़ेगा, जो द्विपक्षीय व्यापार और निवेश के लिए कर परिदृश्य में बदलाव का संकेत है।

स्विट्जरलैंड द्वारा MFN का दर्जा वापस लिया जाना:

- स्विट्जरलैंड के संघीय वित्त विभाग (DFF) ने घोषणा की कि वह स्विट्जरलैंड और भारत के बीच कर संधि में MFN खंड के आवेदन को निलंबित कर देगा, विशेष रूप से दोहरे कराधान से बचाव समझौते (DTAA) के संदर्भ में।

- यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के अक्टूबर 2023 के फैसले के बाद आया है, जिसने प्रभावी रूप से पिछली व्याख्या को उलट दिया था जिसने भारतीय संस्थाओं को स्विट्जरलैंड और अन्य देशों के बीच बाद की कर संधियों के आधार पर कम कर दरों से लाभान्वित होने की अनुमति दी थी।
- इस फैसले के परिणामस्वरूप, जनवरी 2025 से, स्विट्जरलैंड में भारतीय संस्थाओं द्वारा अर्जित आय उच्च कर कटौती दर के अधीन होगी, विशेष रूप से लाभांश पर 10% कर। इससे पहले, MFN क्लॉज ने भारत को स्विट्जरलैंड द्वारा लाभांश पर लागू कम कर दरों का लाभ उठाने की अनुमति दी थी, विशेष रूप से कोलंबिया और लिथुआनिया जैसे देशों के साथ कर संधियों में बदलाव के परिणामस्वरूप।

भारत और स्विट्जरलैंड के मध्य DTC:

- भारत और स्विट्जरलैंड के बीच 30 अगस्त, 2010 को हस्ताक्षरित प्रोटोकॉल के अनुसार, यदि भारत, किसी तीसरे देश, जो OECD (आर्थिक सहयोग और विकास संगठन) का सदस्य है, के साथ किसी समझौते के तहत, लाभांश, ब्याज, रॉयल्टी या तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क पर स्रोत पर अपने कराधान को भारत-स्विट्जरलैंड DTC में उक्त आय मदों पर प्रदान की गई दर से कम दर तक सीमित करता है, तो वही दर स्विट्जरलैंड और भारत के बीच भी उस तारीख से लागू होगी, जिस दिन यह लागू होता है।

- भारत ने 2011 में लिथुआनिया और कोलंबिया के साथ DTC पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत उसने दोनों देशों को 5 प्रतिशत का कर कटौती प्रदान की। इसके बाद, लिथुआनिया और कोलंबिया क्रमशः जुलाई 2018 और अप्रैल 2020 में OECD में शामिल हो गए, इस प्रकार स्विट्जरलैंड और भारत दोनों MFN खंड के तहत एक-दूसरे को 5 प्रतिशत कर कटौती का विस्तार करने के पात्र बन गए।

इस मामले का कानूनी पृष्ठभूमि:

- यह विवाद नेस्ले से जुड़े एक मामले से जुड़ा है, जिसमें भारतीय अदालतों से दोनों देशों के बीच दोहरे कराधान समझौते के प्रावधानों की व्याख्या करने के लिए कहा गया था।
- शुरुआत में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने MFN खंड के माध्यम से अन्य देशों के साथ स्विट्जरलैंड की बाद की संधियों के लाभों को भारत तक बढ़ाने के पक्ष में फैसला सुनाया।
- हालाँकि, सर्वोच्च न्यायालय ने अक्टूबर 2023 में इस फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया कि स्विस-भारत संधि में कम कर दरों का लाभ भारत द्वारा भारतीय आयकर अधिनियम, विशेष रूप से धारा 90 के तहत एक अलग अधिसूचना के बिना स्वचालित रूप से नहीं बढ़ाया जा सकता है।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

- सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय समझौतों से उत्पन्न कर दरों में कोई भी बदलाव तब तक पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सकता जब तक कि भारतीय अधिकारियों द्वारा स्पष्ट रूप से न कहा जाए।
- स्विट्जरलैंड ने इस व्याख्या को स्वीकार करते हुए MFN का दर्जा वापस लेने का फैसला किया, इस प्रकार भारतीय कंपनियों को पहले मिलने वाला तरजीही कर उपचार समाप्त हो गया।

इस निर्णय पर भारतीय व्यवसायों पर प्रभाव:

- स्विट्जरलैंड में परिचालन करने वाली भारतीय कंपनियों को जनवरी 2025 से, यूरोपीय देश में अर्जित आय पर उच्च करों का सामना करना पड़ेगा, विशेष रूप से लाभांश के संबंध में।
- उल्लेखनीय है कि भारत-स्विट्जरलैंड दोहरे कराधान परिहार समझौते के संदर्भ में, MFN खंड एक महत्वपूर्ण प्रावधान था जिसने भारत को अधिक अनुकूल कर शर्तों से लाभान्वित होने की अनुमति दी, खासकर जब स्विट्जरलैंड ने अन्य देशों के साथ अपनी संधियों को अद्यतन किया था।
- इस प्रावधान को वापस लेने का स्विस का निर्णय, कानूनी रूप से उचित होने के बावजूद, भारतीय संस्थाओं के लिए उच्च कर देनदारियों का परिणाम होगा और इस क्षेत्र में उनकी निवेश रणनीतियों को प्रभावित कर सकता है।

दोनों देशों में व्यापक आर्थिक और व्यापार संबंध:

- यह कर परिवर्तन भारत और यूरोपीय देशों के बीच बढ़ते आर्थिक संबंधों के बीच हुआ है। 2023 में, भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA) - जिसमें स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिकटेंस्टीन शामिल हैं - ने एक नया व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता (TEPA) किया।
- इस समझौते का उद्देश्य भारत और EFTA देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना है, जिसमें वस्तुओं, सेवाओं, बौद्धिक संपदा और निवेश सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
- जबकि MFN वापसी भारतीय व्यवसायों के लिए अल्पकालिक चुनौतियां पैदा कर सकती है, लेकिन इससे TEPA की व्यापक क्षमता पर असर नहीं पड़ना चाहिए। इस समझौते के तहत, भारत को बेहतर बाजार पहुँच और विदेशी निवेश प्राप्त होगा, जो स्विट्जरलैंड द्वारा लगाए गए उच्च करों की भरपाई कर सकता है।
- इसके अलावा, भारत यूरोपीय संघ के साथ एक अलग मुक्त व्यापार समझौते पर भी बातचीत कर रहा है, जो आर्थिक विकास के लिए अतिरिक्त अवसर प्रदान कर सकता है।

ला नीना को लेकर भविष्यवाणी में गलती क्यों हुई?

परिचय:

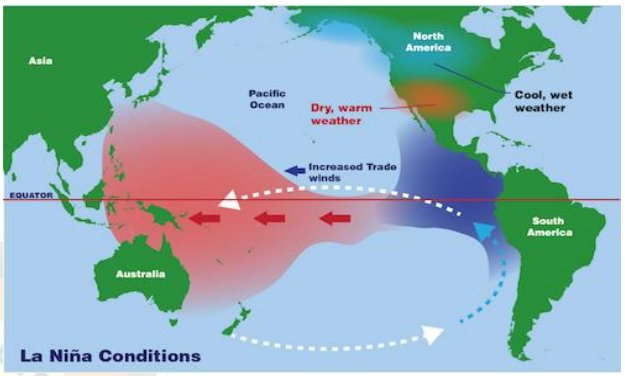

- वर्ष के समाप्त होने में अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, तथा ऐसे पर्याप्त कारण और आंकड़े हैं जो यह सुझाते हैं कि 2024, 2016 को पीछे छोड़ते हुए, अब तक का सबसे गर्म वर्ष हो सकता है। इसके कई कारणों में से एक यह है कि पूर्वानुमानों के बावजूद ला नीना का उदय नहीं होना है।

ला नीना क्या है?

- 'ला नीना' 'एल नीनो दक्षिणी दोलन (ENSO)' के रूप में जाना जाने वाला जलवायवी परिघटना का एक चरण है, जो मध्य और पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर के साथ समुद्र के तापमान में परिवर्तन के साथ-साथ वायुमंडल में उतार-चढ़ाव के कारण होती है।
- ENSO के तीन चरण हैं - गर्म (एल नीनो), ठंडा (ला नीना), और तटस्थ - जो दो से सात वर्षों के अनियमित चक्रों में होते हैं। भारत में, अल नीनो कम वर्षा और

उच्च तापमान से जुड़ा है, जबकि ला नीना अधिक वर्षा और कम तापमान से जुड़ा है।

ENSO के तीन चरणों की प्रक्रिया:

तटस्थ चरण:

- तटस्थ चरण में, प्रशांत महासागर का पूर्वी भाग (दक्षिण अमेरिका के उत्तर-पश्चिमी तट के पास) पश्चिमी भाग (फिलीपींस और इंडोनेशिया के पास) की तुलना में ठंडा होता है।
- यह प्रचलित ट्रेड विंड प्रणालियों के कारण होता है जो पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं, जो समुद्र के गर्म सतह के पानी को इंडोनेशियाई तट की ओर बहा ले जाती हैं, जिसके वजह से नीचे से ठंडा पानी विस्थापित पानी की जगह ऊपर आता है।

अल नीनो चरण:

- अल नीनो चरण में, ट्रेड विंड प्रणालियाँ कमजोर हो जाती हैं, जिससे दक्षिण अमेरिकी तट से गर्म पानी का कम विस्थापन होता है।
- नतीजतन, पूर्वी प्रशांत महासागर सामान्य से ज्यादा गर्म हो जाता है।

ला नीना चरण:

- ला नीना चरण में इसके विपरीत होता है - ट्रेड विंड सामान्य से ज़्यादा तेज़ हो जाती हैं, और बड़ी मात्रा में पानी को पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र की ओर धकेल देती हैं। जिससे प्रशांत महासागर का पूर्वी भाग अपेक्षाकृत ज्यादा ठंडा हो जाता है।

इस वर्ष ENSO के पूर्वानुमान क्या थे?

- इस वर्ष, एकत्रित महासागर संकेतों के आधार पर मौसम मॉडल ने अगस्त-सितंबर के दौरान ला नीना के उभरने की संभावना का सुझाव दिया था। बाद में इन अनुमानों को अपडेट किया गया और अनुमान लगाया गया कि ला नीना अक्टूबर-दिसंबर में उभरेगा।
- हालांकि, नवीनतम अनुमान अब कहते हैं कि दिसंबर और फरवरी के बीच एक छोटा और कमजोर ला नीना उभरेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि कमजोर ला नीना मार्च-मई 2025 तक ENSO के तटस्थ चरण में परिवर्तित हो सकता है।

इस साल ला नीना की भविष्यवाणियाँ क्यों चूक गईं?

- आम तौर पर, समुद्री सतह के तापमान में स्पष्ट परिवर्तन के मामलों में मौसम मॉडल की सटीकता अधिक होती है, यानी, जब मजबूत एल नीनो या ला नीना होने की संभावना होती है।

- इस बार ऐसा होने की संभावना नहीं है, जिसके कारण मौसम मॉडल सही परिणाम नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि वे अपने इनपुट में तापमान में होने वाले छोटे-छोटे बदलावों को ध्यान में नहीं रख पा रहे हैं। इसके अलावा, कुछ अन्य जलवायु संबंधी कारण भी मॉडल के गलत होने में भूमिका निभा सकते हैं।

महासागर-वायुमंडल युग्मन:

- इस वर्ष, महासागर और वायुमंडल के बीच परस्पर क्रिया अपेक्षा के अनुरूप नहीं थी - जिसके कारण भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर के साथ तापमान गर्म या सामान्य के करीब रहा। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि अल नीनो की स्थिति 2024 तक जारी रही, जिसका अर्थ है कि इसका प्रभाव महासागर के तापमान के संदर्भ में जारी रहा। युग्मित महासागर-वायुमंडल प्रणाली ने ENSO-तटस्थ स्थितियों को प्रतिबिंबित किया।

पश्चिमी हवा की विसंगतियाँ:

- समुद्र की सतह के तापमान को बनाए रखने और नियंत्रित करने में वायुमंडल का एक मजबूत संबंध है। सितंबर-अक्टूबर के दौरान, जब ला नीना चरण में संक्रमण की संभावना थी, पश्चिमी हवा की विसंगतियाँ प्रबल थीं। जलवायु विज्ञान की दृष्टि से, पश्चिमी हवा की विसंगतियाँ ला नीना के विकास के लिए प्रतिकूल हैं।

मानसून और ENSO:

- चूंकि एल नीनो चरण समाप्त हो गया है और ENSO तटस्थ चरण भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून की शुरुआत के साथ मेल खाता है, इसलिए इस वर्ष जून-सितंबर में भारत में प्रचुर मात्रा में और सामान्य से अधिक वर्षा हुई। मानसून और ENSO एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। एक अच्छा मानसून पश्चिमी हवा की विसंगतियों को प्रभावित कर सकता है, जो बदले में ला नीना की शुरुआत में देरी/प्रभाव डाल सकता है।

'ला नीना' और भारत में बेहतर मानसूनी वर्षा:

- ला नीना स्थिति में - मध्य और पूर्व-मध्य भूमध्यरेखीय प्रशांत क्षेत्र में समुद्र की सतह के तापमान के ठंडा होने से जुड़ा जलवायु पैटर्न - आमतौर पर भारत में अच्छी मानसूनी वर्षा से जुड़ा होता है। पिछले आंकड़ों से पता चलता है कि 1954 के बाद से पिछले 22 ला नीना वर्षों में से अधिकांश में ग्रीष्मकालीन मानसून या तो 'सामान्य' या 'सामान्य से ऊपर' था।
- वहीं 1951 से 2023 तक के आंकड़ों से पता चलता है कि नौ वर्षों में जब ला नीना के पहले अल नीनो की स्थिति रही हो तो, ग्रीष्मकालीन मानसूनी वर्षा, दो वर्षों में 'सामान्य से ऊपर', पांच वर्षों में 'अतिरिक्त' और दो वर्षों 'सामान्य' के सकारात्मक पक्ष पर में रही है।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

MCQs

1. चर्चा में रहे 'रेलवे (संशोधन) विधेयक 2024' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

   1. यह विधेयक रेलवे बोर्ड को वैधानिक समर्थन प्रदान करने के लिए लाया गया है।
   2. इस विधेयक में वित्तीय और परिचालन संबंधी निर्णय लेने का अधिकार रेलवे जोनों को देने का प्रस्ताव है।

   उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

   (a) केवल 1

   (b) केवल 2

   (c) 1 और 2 दोनों

   (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

   Ans:(c)

2. भारत में रेलवे नेटवर्क का निर्माण स्वतंत्रता से पहले निम्नलिखित किस विभाग की एक शाखा के रूप में शुरू हुई थी?

   (a) वित्त विभाग

   (b) लोक निर्माण विभाग

   (c) सैन्य विभाग

   (d) जहाजरानी विभाग

   Ans:(b)

3. चर्चा में रहे 'स्विट्जरलैंड द्वारा भारत से MFN का दर्जा वापस लिये जाने' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. इससे 1 जनवरी, 2025 से, स्विट्जरलैंड में भारतीय व्यवसायों को विशेष रूप से लाभांश आय पर उच्च कर कटौती दरों का सामना करना पड़ेगा।
2. यह निर्णय स्विस खाद्य कंपनी नेस्ले से जुड़े कर विवाद के संबंध में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रतिकूल फैसले के बाद आया है।

उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Ans:(c)

4. वर्ष 2024 में एक अच्छे ला नीना की संभावना व्यक्त की गयी थी। लेकिन निम्नलिखित किस/किन कारण/कारणों से इस साल ला नीना की भविष्यवाणियाँ चूक गईं?

(a) महासागर और वायुमंडल के बीच परस्पर क्रिया अपेक्षा के अनुरूप नहीं थी।

(b) सितंबर-अक्टूबर के दौरान पछुआ हवा प्रणाली में विसंगतियाँ प्रबल थीं।

(c) एक अच्छी मानसून ने ला नीना की शुरुआत में प्रभाव डाला है।

(d) उपर्युक्त सभी सही हैं।

Ans:(d)

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

5. चर्चा में रहे 'एल नीनो दक्षिणी दोलन (ENSO)' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. ENSO के तीन चरण, गर्म (एल नीनो), ठंडा (ला नीना), और तटस्थ होते हैं।
2. भारत में, अल नीनो अधिक वर्षा और कम तापमान से, जबकि ला नीना कम वर्षा और अधिक तापमान से जुड़ा है।

उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Ans:(a)